

चुनावी बॉण्ड

प्रलिस के लयः

चुनावी बॉण्ड ।

मेन्स के लयः

चुनावी बॉण्ड, इलेक्शन फंडगि, राजनीतके अपराधीकरण से जुड़े मुद्दे ।

चर्चा में क्यों?

पाँच राज्यों में आगामी वधानसभा चुनावों से पहले **चुनावी बॉण्ड** (Electoral Bonds) की 19वीं कश्ति, जसि नकद वकिल्प के रूप में पेश कया कया जाता है, की बक्री की गई ।

- पछिले दनों सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड के जरयि राजनीतके दलों को मली धनराशके दुरुपयोग पर आशंका जताई है ।
- यह चुनावी फंडगि में पारदर्शता लाने और राजनीतके अपराधीकरण पर रोक लगाने हेतु भी इन बॉण्डों को पेश करने के मूल वचार को खंडति कर सकता है ।

प्रमुख बडि

चुनावी बॉण्ड के बारे में:

- चुनावी बॉण्ड बना कसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी कयि जाते हैं ।
- भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्डों को जारी करने और भुनाने (Encash) के लयि अधिकृत बैंक है, ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दनों तक वैध रहते हैं ।
- यह बॉण्ड इन्हें एक पंजीकृत राजनीतके पार्टी के नरिदषिट खाते में प्रतदिय होता है ।
- बॉण्ड कसी भी वयकृता (जो भारत का नागरक है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दनों की अवधि हेतु खरीद के लयि उपलब्ध होते हैं, जैसा ककेंद्र सरकार द्वारा नरिदषिट कया गया है ।
- एक वयकृता या तो अकेले या अन्य वयकृतियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है ।
- बॉण्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं कया जाता है ।

संबंधति मुद्दे:

- लोकतंत्र के लयि झटका:** वतित अधनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतके दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त चंदे का खुलासा करने से छूट दी है ।
 - इसका मतलब है क मतदाता यह नहीं जान पाएंगे क कसि वयकृता, कंपनी या संगठन ने कसि पार्टी को और कसि हद तक वतितपोषति कया है ।
 - हालाँक एक प्रतनिधि लोकतंत्र में नागरक उन लोगों को वोट देना पसंद करते हैं जो संसद में उनका प्रतनिधित्व करेंगे ।
- जानने के अधिकार से समझौता:** भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार कया है क "जानने का अधिकार" (Right To Know) वषिष रूप से चुनावों के संदर्भ में भारतीय संवधान के तहत अभवियकृता की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभन्न अंग है ।
- स्वतंत्र और नषिपकष चुनावों के खलाफ:** चुनावी बॉण्ड नागरकों को इस संदर्भ में कोई वविरण नहीं देते हैं ।
 - उक्त गुमनामी उस समय की सरकार पर लागू नहीं होती है, जो भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से डेटा की मांग करके हमेशा दाता के वविरण तक पहुँच सकती है ।
 - इसका मतलब यह है क सत्ता में बैठी सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र व नषिपकष होने वाले चुनाव को बाधति कर सकती है ।
- करोनी कैपटिलजिम:** चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतके चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अछे संसाधन वाले नगिर्मों को चुनावों के लयि धन देने की अनुमति देती है जसिसे करोनी कैपटिलजिम का मार्ग प्रशस्त होता है ।

आगे की राह:

- **चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता:** कई उन्नत देशों में चुनावों को सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित किया जाता है। यह समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है।
 - **2nd ARC, दनिश गोस्वामी समिति** और कई अन्य ने भी चुनावों हेतु राज्य के लिये वित्तपोषण की सिफारिश की है।
 - इसके अलावा जब तक चुनावों को सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित नहीं किया जाता है, तब तक राजनीतिक दलों को वित्तीय योगदान पर सीमाएँ लागू हो सकती हैं।
- **न्यायपालिका का रेफरी/अंपायर के रूप में कार्य करना:** एक कार्यशील लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के लिये रेफरी/अंपायर के रूप में कार्य करना है।
 - चुनावी बॉण्ड ने सरकार की चुनावी वैधता पर सवाल खड़े कर दिये हैं और इस तरह पूरी चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं।
 - इस संदर्भ में न्यायालयों को एक रेफरी/अंपायर के रूप में कार्य करना चाहिये और लोकतंत्र के ज़मीनी नियमों को लागू करना चाहिये।
- **नागरिक संस्कृति की ओर ट्रांज़ीशन:** भारत लगभग 75 वर्षों से लोकतंत्र के रूप में बेहतर तरीके से काम कर रहा है।
 - अब सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिये मतदाताओं को स्वयं जागरूक होकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों तथा पार्टियों को खारज करना चाहिये।

स्रोत: द हट्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/electoral-bonds-7>

